बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
29 अक्टूबर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 277
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com
Website: dunvalleymail.com
डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

सड़कों पर वीआईपी वाहन, फुटपाथ पर दुकानें

◆मरीजों को ले जाती एंबुलेंसी को नहीं मिलता रास्ता

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। दून की सड़कों पर आम आदमी का चलना मुश्किल है। कहीं वीआईपी वाहनों का सड़क के बीचोंबीच जमावड़ा है, तो कहीं फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा। नतीजा यह कि पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है और वाहन चालकों को कदम-कदम पर जाम से जूझना पड़ता है। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें परेशानी आमजन की है, लेकिन व्यवस्था की जवाबदेही तय होती नजर नहीं आती।

देहरादून की पहचान कभी अपेक्षाकृत शांत और व्यवस्थित शहर के रूप में होती थी। आज शहर की व्यस्त सड़कों पर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं। बाजारों में खरीदारी के लिए निकले लोग हों, दफ्तर पहुंचने की जल्दबाजी में कर्मचारी या स्कूल-कालेज जाने वाले विद्यार्थी हर किसी को जाम के झाम से गुजरना पड़ता है। कई जगह सड़क के किनारे खड़े वाहन और फुटपाथ पर फैली दुकानें पहले से सीमित रास्ते को और संकरा कर देती हैं।

◆व्यवस्था नहीं बदलती और जनता यूं ही पिस रही
◆देहरादून की यातायात व्यवस्था पर उठे कई सवाल
◆जाम में फंसता आम आदमी तो जवाबदेही किसकी

शहर में यातायात की समस्या का एक बड़ा पहलू बेतरतीब पार्किंग है। वीआईपी और अन्य वाहनों के सड़क किनारे या सड़क के बीचोंबीच खड़े होने से यातायात की रफ्तार प्रभावित होती है। जहां वाहन खड़े करने के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं हैं या उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, वहां सड़क ही पार्किंग स्थल बन जाती है। सवाल यह है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह वाहन खड़े करने की छूट आखिर किस आधार पर मिलती है? नियम यदि आम नागरिक के लिए हैं, तो उनका पालन रसूखदारों से भी क्यों नहीं कराया जाता? दूसरी ओर, फुटपाथ पर दुकानों और अस्थायी कारोबार का फैलाव पैदल चलने वालों के अधिकार को सीमित कर रहा है। फुटपाथ का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रास्ता देना है, न कि उसे व्यापारिक गतिविधियों के लिए खुला छोड़ देना। जब फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं बचती, तो पैदल यात्रियों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है। इससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।

जाम का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है, जिनके पास समय और संसाधनों की सीमित गुंजाइश होती है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी देर से पहुंचते हैं, विद्यार्थियों की दिनचर्या प्रभावित होती है और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो सकती है। ईंधन की बर्बादी और वाहनों से निकलने वाला धुआं अलग समस्या है। यानी अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग का नुकसान केवल कुछ मिनट की देरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और नागरिकों की दिनचर्या पर भी पड़ता है।

सबसे बड़ा सवाल नगर निगम, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर है। यदि फुटपाथ पर अतिक्रमण है, तो उसे हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि सड़क पर वाहन बेतरतीब खड़े हैं, तो चालान और कार्रवाई क्यों प्रभावी नहीं दिखती? और यदि किसी खास व्यक्ति या वाहन को नियमों से छूट मिल रही है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? शहर की यातायात व्यवस्था केवल त्योहारों, विशेष आयोजनों या वीआईपी आवागमन के दौरान सक्रिय रहने से नहीं सुधर सकती। इसके लिए रोजाना निगरानी और नियमों का समान रूप से पालन जरूरी है।

देहरादून में यातायात का दबाव बढ़ने के साथ पार्किंग स्थलों की उपलब्धता, फुटपाथों की सुरक्षा और बाजारों में अतिक्रमण का समाधान प्राथमिकता बनना चाहिए। अवैध पार्किंग पर नियमित कार्रवाई, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ खाली रखने, दुकानदारों के लिए निर्धारित स्थानों की व्यवस्था और व्यस्त बाजारों में यातायात प्रबंधन जैसे कदम जरूरी हैं। केवल अभियान चलाकर कुछ दिन रास्ते खाली करा देना स्थायी समाधान नहीं है। कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के लागू होनी चाहिए।

राजधानी होने का अर्थ केवल सरकारी कार्यालयों और वीआईपी आवाजाही का

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

चुनाव आते ही निशाने पर कांग्रेस का 'अतीत'

◆सीएम धामी के बयानों से प्रदेश की राजनीति में चुनावी संघर्ष की आहट

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में चुनावी संघर्ष की आहट तेज कर दी है। कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए धामी ने कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस के पाप धोने का काम कर रही है और सफाई आगे भी जारी रहेगी। यह महज एक राजनीतिक तंज नहीं, बल्कि विपक्ष को उसके अतीत के कठघरे में खड़ा करने की रणनीति का संकेत है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा भ्रष्टाचार के सवाल पर कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में लाना चाहती है, जबकि कांग्रेस मौजूदा सरकार की जवाबदेही को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है।

इस राजनीतिक टकराव की खास बात यह है कि दोनों दल भ्रष्टाचार को हथियार बना रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए यही मुद्दा राजनीतिक परीक्षा भी बन सकता है। भाजपा कांग्रेस के शासनकाल और पुराने विवादों का हिसाब मांगना चाहती है। कांग्रेस का जोर मौजूदा सरकार पर लगे आरोपों और उन पर कार्रवाई की स्थिति को लेकर सवाल उठाने पर है। अब मुकाबला केवल आरोप लगाने का नहीं, बल्कि अपने दावों को तथ्यों से साबित करने का है।

मुख्यमंत्री के बयान के राजनीतिक मायने उनकी भाषा से आगे जाते हैं। भाजपा कांग्रेस को केवल कमजोर विपक्ष के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे दल के रूप में पेश करना चाहती है, जिसे भ्रष्टाचार और पुराने विवादों पर जवाब देना चाहिए। इस रणनीति से कांग्रेस के लिए सरकार की आलोचना करते समय अपने शासनकाल का बचाव करना भी जरूरी हो जाता है। धामी का संदेश यह है कि कांग्रेस यदि भाजपा सरकार से हिसाब मांगती है, तो उसे अपने अतीत के सवालों का सामना भी करना होगा। यह चुनावी राजनीति का जाना-पहचाना तरीका है विपक्ष के वर्तमान आरोपों का जवाब उसके पुराने रिकॉर्ड से देना। लेकिन इसकी सीमा भी है। किसी पूर्ववर्ती सरकार पर लगे

◆कांग्रेस के पाप धो रही प्रदेश सरकार के बयान से विपक्ष ने बढ़ाया दबाव
◆प्रदेश में अब तक के भ्रष्टाचार के आरोपों पर दलों को देना होगा हिसाब

आरोप मौजूदा सरकार के कामकाज का स्वत: प्रमाणपत्र नहीं बन जाते। भाजपा को अपनी उपलब्धियों और जवाबदेही का हिसाब अलग से देना होगा।

हरक सिंह रावत से जुड़े जैनी प्रकरण का उल्लेख इस सियासी बहस को और संवेदनशील बनाता है। ऐसे विवाद नेताओं की सार्वजनिक छवि और राजनीतिक विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा के लिए यह कांग्रेस से जुड़े नेताओं पर सवाल उठाने का अवसर है, जबकि कांग्रेस के लिए अपने नेताओं के पक्ष को स्पष्ट करने की चुनौती। लेकिन यहां राजनीतिक आरोप और कानूनी निष्कर्ष के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। उपलब्ध पुष्ट जानकारी के आधार पर इस प्रकरण को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का निर्णायक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। किसी भी आरोप की गंभीरता का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों, जांच और कानूनी निष्कर्षों से ही होना चाहिए। यही भाजपा की रणनीति की कसौटी भी है। यदि पार्टी पुराने विवादों को चुनावी मुद्दा बनाती है, तो उसे तथ्य सामने रखने होंगे। केवल आरोप दोहराने से राजनीतिक शोर तो पैदा हो सकता है, लेकिन उससे जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती।

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसके फैसलों की जांच करना है। लेकिन इस भूमिका का प्रभाव तभी बढ़ता है, जब विरोध के साथ ठोस तथ्य, स्पष्ट मांगें और वैकल्पिक नीतियां भी सामने रखी जाएं। सदन में हंगामे के बीच 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और विभिन्न विधायी प्रस्ताव पारित हुए। सत्र के दौरान विपक्ष ने चर्चा की मांग उठाई, जबकि सरकार ने विधायी कार्यवाही आगे बढ़ाई। इस घटनाक्रम ने यह प्रश्न भी छोड़ा कि भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त तथा सार्थक चर्चा हो पाई या नहीं। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रमाणों और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखे। उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि सत्ता में आने पर

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

महंगाई बेलगाम, राहत तीन प्रतिशत

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर राहत का दांव चला है। निश्चित रूप से बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनके घरेलू बजट को कुछ सहारा देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई की मार के सामने यह बढ़ोतरी पर्याप्त है? जब रसोई से लेकर अस्पताल, स्कूल और बाजार तक खर्च का दबाव बना हुआ है, तब तीन प्रतिशत की वृद्धि कितनी दूर तक राहत पहुंचा पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वेतन में बढ़ी रकम बाजार की महंगाई निगल जाए और महीने के अंत में कर्मचारी का बजट फिर उसी मोड़ पर खड़ा मिले? महंगाई भत्ता कोई सरकारी उपकार नहीं, बल्कि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की क्रयशक्ति को बचाए रखने की व्यवस्था है। इसलिए इसे राहत के बड़े सरकारी ऐलान के रूप में पेश करने से अधिक जरूरी है, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करना। कर्मचारी की आय में बढ़ोतरी तभी सार्थक है, जब वह पहले की तुलना में अधिक जरूरी सामान खरीद सके, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च उठा सके और महीने के अंत में उसके पास कुछ बचत भी बचे। यदि बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा महंगे राशन, बिजली के बिल, दवाओं, परिवहन और फीस में खप जाए, तो बढ़ोतरी का लाभ आखिर कितना रह जाता है? महंगाई की असली चोट कीमतों में नहीं, घटती क्रयशक्ति में दिखाई देती है। आमदनी बढ़ने के बावजूद यदि परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जाए, तो आय में वृद्धि का दावा अधूरा है। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि महंगाई की वास्तविक मार किस स्तर पर पड़ रही है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर होती है, इसलिए अलग-अलग वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि अलग होगी। इसके साथ ही भुगतान की तारीख, लागू दर और परिवार के खर्चों का अंतर भी वास्तविक लाभ तय करता है। सरकार के सामने चुनौती केवल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने की भी है, जिनके कारण आम परिवार का बजट लगातार दबाव में रहता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, मकान का किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च परिवार की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में राहत के बिना वेतन और भत्तों में होने वाली वृद्धि का बड़ा हिस्सा अतिरिक्त खर्च में समा सकता है। आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़ों से ज्यादा मायने यह रखता है कि उसकी थाली, इलाज और बच्चों की पढ़ाई कितनी सुलभ है। इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अक्सर सरकारी घोषणाओं के शोर में पीछे छोड़ दिया जाता है। महंगाई का सामना केवल केंद्रीय कर्मचारी नहीं करते। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, छोटे दुकानदार, खेतिहर मजदूर और स्वरोजगार पर निर्भर लोग भी उसी बाजार से सामान खरीदते हैं। लेकिन उनकी आय न नियमित है और न ही उसमें महंगाई के अनुरूप वृद्धि की कोई सुनिश्चित व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में कुछ सुरक्षा मिलती है, जबकि करोड़ों परिवारों के लिए आमदनी और खर्च के बीच बढ़ती खाई को पाटने का कोई भरोसेमंद सहारा नहीं होता। यही वह बिंदु है, जहां सरकार की आर्थिक नीति की व्यापकता पर सवाल उठता है। क्या महंगाई से राहत की जिम्मेदारी केवल वेतनभोगी वर्ग तक सीमित रहनी चाहिए? क्या उस मजदूर की चिंता कम महत्वपूर्ण है, जिसकी मजदूरी बढ़ती कीमतों के साथ नहीं बढ़ती? क्या उस परिवार की परेशानी कम है, जिसे इलाज के लिए अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है या बच्चों की पढ़ाई के खर्च में कटौती करनी पड़ती है? आर्थिक न्याय का तकाजा है कि महंगाई से निपटने की नीति में इन वर्गों को भी केंद्र में रखा जाए। सरकार को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति मजबूत करने, जमाखोरी पर नियंत्रण, रोजगार के अवसर बढ़ाने, श्रमिकों की आय में सुधार और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। महंगाई पर नियंत्रण केवल आंकड़ों का खेल नहीं हो सकता। इसका असर लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें परिवारों की आय से तेज गति से बढ़ती हैं, तो वेतन में होने वाली वृद्धि भी स्थायी राहत देने में नाकाम हो सकती है। यह भी जरूरी है कि महंगाई भत्ते की घोषणा को राजनीतिक उपलब्धि के बजाय कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाए। कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलना चाहिए और वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह बताना होगा कि बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ता को राहत देने की उसकी व्यापक योजना क्या है। केवल आय के एक हिस्से में वृद्धि करके महंगाई के मूल दबाव से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन इसे महंगाई के खिलाफ निर्णायक जीत कहना वास्तविकता से मुंह मोड़ना होगा। कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त आय है, मगर महंगाई के सामने इसकी पर्याप्तता का फैसला बाजार और घरेलू बजट करेंगे। सरकार की सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता कि उसने कितने प्रतिशत भत्ता बढ़ाया। असली कसौटी यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी की क्रयशक्ति कितनी बची और आम नागरिक की जिंदगी कितनी आसान हुई। सरकारी घोषणा में तीन प्रतिशत की राहत है, लेकिन जनता की कसौटी पर सवाल पूरा महीना निकालने का है। जब तक आम परिवार जरूरी खर्चों के बाद बचत करने की स्थिति में नहीं पहुंचता, तब तक महंगाई से राहत के दावे अधूरे रहेंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी आर्थिक नीति, जिसमें आमदनी बढ़ने का अर्थ केवल वेतन-पर्ची पर अधिक रकम नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक राहत हो।

चुनाव सिर पर और सत्ता 'बेखबर'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज हो रही है। भाजपा सत्ता में वापसी के लिए संगठन को धार देने और अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को घेरकर सत्ता में लौटने की जमीन तलाश रही है। लेकिन चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक समीकरणों और सत्ता के दावों के बीच राजधानी देहरादून की सड़कें एक अलग ही कहानी कह रही हैं। उत्तराखंड की राजनीति में राजधानी का अपना महत्व है। देहरादून केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की सत्ता, नौकरशाही और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों तक की मौजूदगी इसी शहर में रहती है। इसके बावजूद आम नागरिक का जाम से जूझना, फुटपाथ पर सुरक्षित रास्ता नहीं मिलना और पार्किंग की अव्यवस्था से परेशान होना राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़े करता है। यह परेशानी अब केवल यातायात तक सीमित नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं से जुड़ा राजनीतिक प्रश्न बन सकती है।

प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लिहाजा देहरादून की यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण पर उठने वाले सवालों की सीधी राजनीतिक जिम्मेदारी सरकार पर आएगी। भाजपा 2027 के चुनाव में विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व को अपनी ताकत के रूप में पेश करना चाहेगी। लेकिन विपक्ष के पास यह पूछने का अवसर रहेगा कि जब राजधानी में ही सड़क और फुटपाथ व्यवस्थित नहीं हो पा रहे, तो विकास के दावों का लाभ आम नागरिक तक किस हद तक पहुंचा है? वीआईपी वाहनों की बेतरतीब पार्किंग का सवाल इस बहस को और राजनीतिक बनाता है। यदि आम नागरिक के वाहन पर नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई होती है, तो रसूखदारों के मामले में भी वैसी ही सख्ती क्यों नहीं दिखाई देनी चाहिए? सार्वजनिक सड़क किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। नियमों का पालन सबके लिए समान होना चाहिए। यदि प्रशासनिक कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव दिखाई देता है, तो यह सरकार की छवि और कानून के समान अनुपालन-दोनों के लिए चुनौती बनता है।

भाजपा के सामने इसलिए दोहरी चुनौती है। उसे एक ओर अपने विकास कार्यों का राजनीतिक बचाव करना होगा, तो दूसरी ओर उन कमियों पर भी जवाब देना होगा, जो नागरिकों को रोजाना परेशान करती हैं। चुनाव से पहले इन समस्याओं का समाधान करना सरकार के लिए केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का अवसर भी है। विपक्षी कांग्रेस के लिए देहरादून की बदहाल यातायात व्यवस्था सरकार को घेरने का मुद्दा बन सकती है। रोजगार, महंगाई, पलायन और बुनियादी सुविधाओं के सवालों के साथ राजधानी में जाम और अतिक्रमण की समस्या को जोड़कर कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा सकती है। यह ऐसा मुद्दा है, जिसे जनता को समझाने के लिए लंबे राजनीतिक भाषणों की जरूरत नहीं। नागरिक खुद सड़कों पर इसकी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने भी राजनीतिक चुनौती कम नहीं है। केवल भाजपा को कठघरे में खड़ा करने से सत्ता का रास्ता नहीं खुलेगा। उसे यह बताना होगा कि उसकी सरकार बनने पर शहर की यातायात व्यवस्था कैसे बदलेगी, पार्किंग की समस्या का समाधान क्या होगा, फुटपाथों को अतिक्रमण से कैसे मुक्त रखा जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर बिना भेदभाव कार्रवाई कैसे सुनिश्चित होगी।

विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है कि वह विरोध की राजनीति से आगे बढ़कर वैकल्पिक शहरी नीति पेश करे। यदि कांग्रेस इन मुद्दों को केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित रखती है, तो जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। देहरादून की अव्यवस्था का सबसे तीखा राजनीतिक पहलू वीआईपी संस्कृति और आम नागरिक के अनुभव के बीच का अंतर है। सत्ता के गलियारों में बैठकों, योजनाओं और विकास के दावों पर चर्चा होती है, जबकि सड़क पर निकलने वाला नागरिक जाम में अपना समय गंवाता है। फुटपाथ पर कब्जे के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में यह असंतुलन एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि क्या राजधानी की व्यवस्था आम जनता की सुविधा के लिए है या प्रभावशाली लोगों की सहूलियत के हिसाब से चल रही है?

◆2027 की जंग से पहले प्रदेश की बदहाली भाजपा के लिए चुनौती
◆कांग्रेस के लिए सियासी हथियार से व्यवस्था पर उठाती रही सवाल
◆सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब मांग रही है प्रदेश की आम जनता

यह सवाल चुनावी राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नागरिकों का शासन से सीधा संपर्क इन्हीं रोजमर्रा की परिस्थितियों में होता है। बड़ी परियोजनाएं और घोषणाएं राजनीतिक विमर्श में जगह बना सकती हैं, लेकिन सड़क पर रोज होने वाली परेशानी शासन के प्रति नागरिक की धारणा को भी प्रभावित करती है। हालांकि, इस असंतोष का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, यह स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों और दूसरे मुद्दों पर भी निर्भर करेगा।

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने शहरी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की चुनौती होगी। देहरादून का विस्तार, बढ़ता यातायात, पार्किंग की कमी और फुटपाथों पर अतिक्रमण ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान केवल अस्थायी अभियान से नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घकालीन नियोजन, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने, पार्किंग व्यवस्था विकसित करने और नगर निगम तथा यातायात पुलिस के बीच प्रभावी समन्वय की जरूरत है। राजनीतिक दलों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित तो नहीं रहेगी और क्या सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली लोगों पर भी समान कार्रवाई होगी। साथ ही, छोटे कारोबारियों की आजीविका और पैदल यात्रियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? इन सवालों के जवाब किसी भी राजनीतिक दल की शहरी नीति की गंभीरता को सामने लाएंगे।

2027 का चुनाव अभी भविष्य में है, लेकिन उसकी राजनीतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा के लिए चुनौती अपने शासन की उपलब्धियों के साथ उन समस्याओं का जवाब देना है, जिन्हें जनता रोज महसूस करती है। कांग्रेस के लिए अवसर इन समस्याओं को सरकार की जवाबदेही से जोड़ने और ठोस विकल्प पेश करने का है। दोनों दलों के लिए यह समझना जरूरी होगा कि राजधानी की अव्यवस्था केवल नगर निगम या यातायात पुलिस का विषय बताकर राजनीतिक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। चुनावी सवाल साफ हैकृभाजपा विकास के दावों के बीच राजधानी की बदहाली का जवाब कैसे देगी और कांग्रेस इस बदहाली को सत्ता परिवर्तन के मुद्दे में बदलने के लिए क्या ठोस विकल्प रखेगी? देहरादून की सड़कें फिलहाल किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं सुना रहीं। लेकिन वह सत्ता और विपक्ष, दोनों से जवाब जरूर मांग रही हैं। 2027 में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक रूप लेगा, यह आने वाले महीनों में दलों की रणनीति और प्रशासन की कार्रवाई से स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना तय है कि राजधानी की सड़कों पर आम आदमी की परेशानी को अनदेखा करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा और इसे चुनावी मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस भी समाधान की जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगी।

आज 9 जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट

हमारे संवाददाता

देहरादून। करवा चौथ के दिन उत्तराखंड में मौसम ने बड़ी टेंशन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।

मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और टिहरी में बारिश के आसार हैं। साथ ही 10 जिलों में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है।

देहरादून और नैनीताल में पूरे दिन बादल और हल्की बारिश की संभावना है, इसलिए कई जगहों पर चांद सीधे नहीं दिखेगा। पंडितों के अनुसार बादल होने पर चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है।

धन-धान्य कृषि योजना की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज, एक सप्ताह में सुधार के निर्देश

अल्मोड़ा(आरएनएस)। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नाराजगी जताई है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने और आगामी एक सप्ताह के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना और किसानों को विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है। ऐसे में जरूरी है कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई दे और पात्र लाभार्थियों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। विभागीय स्तर पर आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं की प्रगति में तेजी लाई जाए तथा अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ देवरिया के वार्ड वासियों ने किया प्रदर्शन

रुद्रपुर(आरएनएस)। देवारिया के वार्ड एक और दो के निवासियों ने किशनपुर स्थित श्रीशीतला वेंचर लिमिटेड (इथेनॉल फैक्ट्री) के खिलाफ प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, राख, भूरे कणों, दूषित पानी और तेज शोर से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारी गौरव पांडे को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने उपजिलाधिकारी पहुंच कर प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम गौरव पांडे को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि इथेनॉल फैक्ट्री से आसपास के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और राख के कारण घर-आंगन, वाहनों, खेतों तथा आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार उड़ने वाली राख और धूल से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने फैक्ट्री से दूषित जल निकालने का आरोप लगाते हुए आसपास की भूमि और जलस्रोतों के प्रभावित होने की आशंका जताई। वार्डवासियों ने फैक्ट्री की स्थापना, भूमि उपयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और संचालन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों से फैक्ट्री के प्रदूषण की जांच कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रताप सिंह धानक, रणजीत सिंह नगरकोटी, चंदन पांडे, त्रिलोक सिंह नेगी, खेम सिंह बिष्ट, कुंदन सिंह नेगी, मदन सिंह नेगी, केशव तिवारी, हंसी बिष्ट, सरस्वती बिष्ट, मंजू बिष्ट, गीता नेगी, विमला नेगी, अर्चना नेगी, पिंकी नेगी, ज्योति नेगी, मीना नेगी, कमला पाठक, खष्टी देवी, नेहा डसीला, रमा नेगी, मुन्नी बिष्ट, हेमा पांडेय आदि रहे।

कोदा-झंगोरा से बलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। मयकोटी में राइंका जवाहर नगर में मोटे अनाजों को लेकर हुई कार्यशाला में छात्र-छात्राओं व स्थानीय महिला समूहों को मिलेट की महत्ता बताई। साथ ही उसके व्यवसाय आदि की जानकारी दी गई। कहा गया कि कोदा-झंगोरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलेंगे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।पारंपरिक मोटे अनाजों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने व उन्हें राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मयकोटी के राजकीय इंटर कॉलेज जवाहर नगर में आयोजित कार्यशाला का समापन हो गया। रिपब्लिक फाउंडेशन सोसाइटी और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के माध्यम से आयोजित कार्यशाला में छात्र-छात्राओं और महिला समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को मंडुवा और झंगोरा जैसे मोटे अनाजों के पोषण मूल्य, वैज्ञानिक प्रोसेसिंग, बेहतर क्वालिटी कंट्रोल, आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यशाला के आयोजक सचिव डॉ. सचि नेगी ने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित कौशल विकास ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे सही तरीका है। प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय किसानों, युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को खुद का छोटा उद्योग शुरू करने के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर एमआईटी के निदेशक डॉ. शक्ति सिंह बर्त्वाल, शिक्षक भगवान सिंह रावत, धीरेंद्र सिंह बर्त्वाल, अनूप नेगी, पूनम, जगदंबा चमोला, मातबर सिंह नेगी, धर्मानंद चमोला, मंजरी नेगी, स्वदेश राज, संध्या आदि उपस्थित थे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

टिकटों की जंग से बदलेगा 'चुनावी गणित'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछने लगी है। सत्ता की हैट्रिक लगाने की रणनीति बना रही भाजपा हो या सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए कांग्रेस, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि सही प्रत्याशियों के चयन की भी होगी। टिकट वितरण में जरा-सी चूक कई सीटों पर जीत की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान, आम आदमी पार्टी की सक्रियता और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की नई पार्टी बनाने की घोषणा ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहेगा या छोटे दलों और नए राजनीतिक विकल्पों की दस्तक समीकरणों में बड़ा बदलाव लाएगी?

उत्तराखंड की राजनीति में अब तक सत्ता का मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। राज्य गठन के बाद दोनों दल बारी-बारी से सरकार बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार चुनावी परिदृश्य में कई ऐसे कारक उभर रहे हैं, जो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। क्षेत्रीय अस्मिता, बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की असमानता और स्थानीय नेतृत्व की उपेक्षा जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। इन मुद्दों पर छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की रणनीति भी बड़े दलों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। भाजपा के लिए 2027 का चुनाव सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर तैयारी और चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी है। लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच टिकट वितरण सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, क्षेत्रीय जनाधार, जनता की नाराजगी, संगठन के भीतर दावेदारों की संख्या और जातीय-सामाजिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा।

सत्तारूढ़ दल के पास सरकार के कामकाज को उपलब्धियों के रूप में पेश करने का अवसर है, लेकिन उसे सत्ता विरोधी रुझान की आशंका से भी निपटना होगा। यदि किसी सीट पर मौजूदा विधायक के खिलाफ असंतोष है तो टिकट बदलने का दबाव बनेगा। वहीं, टिकट काटे जाने की स्थिति में नाराज दावेदार निर्दलीय उतर सकते हैं या किसी दूसरे दल का रुख कर सकते हैं। भाजपा के लिए चुनौती केवल मजबूत उम्मीदवार चुनने की नहीं, बल्कि टिकट से वंचित नेताओं और उनके समर्थकों को एकजुट रखने की भी होगी। कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। पार्टी के सामने भाजपा के खिलाफ जन असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने का अवसर है, लेकिन इसके लिए उसे संगठनात्मक एकजुटता और मजबूत उम्मीदवारों की जरूरत होगी। गुटीय खींचतान, कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार और स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा टिकट वितरण को मुश्किल बना सकती है।

कांग्रेस यदि समय रहते उम्मीदवारों की पहचान, क्षेत्रवार रणनीति और चुनावी मुद्दों पर स्पष्टता कायम करती है तो मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। इसके विपरीत, टिकट घोषित होने के बाद बगावत और असंतुष्ट नेताओं की सक्रियता पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के लिए यह भी अहम होगा कि वह केवल भाजपा विरोध के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर अपना ठोस विकल्प जनता के सामने रखे। उत्तराखंड क्रांति दल का सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकले यूकेडी के पास क्षेत्रीय अस्मिता और पहाड़ के हितों की राजनीति करने की विरासत है। लेकिन इस विरासत को चुनावी सफलता में बदलना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

◆भाजपा और कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती
◆यूकेडी का 70 सीटों पर लड़ने का एलान से बढ़ी चिंता
◆आप और उमेश कुमार की नई पार्टी से बढ़ेगी हलचल

राज्य गठन के बाद यूकेडी अपनी आंदोलनकारी पहचान को व्यापक जनाधार में बदलने में सफल नहीं रहा। संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व की चुनौतियां और चुनावों में सीमित प्रभाव ने उसे सत्ता के मुख्य मुकाबले से दूर रखा। अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी को मजबूत उम्मीदवार, बूथ स्तर का संगठन, पर्याप्त संसाधन और स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा तैयार करना होगा। यूकेडी की असली परीक्षा यह होगी कि वह पहाड़ के मुद्दों को केवल भावनात्मक अपील तक सीमित रखता है या उन्हें रोजगार, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, पलायन रोकने और विकेंद्रीकृत विकास की व्यावहारिक योजना से जोड़ पाता है। यदि पार्टी कुछ क्षेत्रों में भी प्रभावी जनाधार तैयार कर लेती है तो वह भाजपा और कांग्रेस के मतों में सेंध लगा सकती है। हालांकि, उसका प्रभाव किस सीट पर किस दल को नुकसान पहुंचाएगा, यह स्थानीय उम्मीदवारों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी चुनावी मुकाबले में एक अतिरिक्त आयाम जोड़ सकती है। पार्टी के सामने दिल्ली और पंजाब के अनुभव को उत्तराखंड की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रस्तुत करने की चुनौती होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उसका प्रचार कितना असर पैदा करता है, यह उसके संगठन, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता से तय होगा। पिछले चुनावी अनुभवों से स्पष्ट है कि केवल प्रचार और राजनीतिक दावों के आधार पर उत्तराखंड में मजबूत जनाधार बनाना आसान नहीं है। इसी क्रम में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा पर भी निगाहें रहेंगी। एक निर्दलीय विधायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके उमेश कुमार के सामने अब व्यक्तिगत जनाधार को संगठनात्मक ताकत में बदलने की चुनौती होगी। नई पार्टी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतार पाती है, उसका राजनीतिक एजेंडा क्या होता है और उसे दूसरे क्षेत्रों में कितना समर्थन मिलता है। नई पार्टी के गठन से स्थानीय स्तर पर नए समीकरण बन सकते हैं। खासकर उन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है, जहां किसी उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी के पारंपरिक जनाधार से अधिक महत्वपूर्ण हो। लेकिन किसी एक क्षेत्र में मिली सफलता को पूरे प्रदेश में विस्तार की गारंटी नहीं माना जा सकता।

2027 के चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि उनके उम्मीदवार कहां मजबूत हैं और किन सीटों पर भाजपा या कांग्रेस के असंतुष्ट नेता उनके साथ जुड़ते हैं। उत्तराखंड की कई सीटों पर जीत का अंतर कम रहने की स्थिति में मतों का सीमित बंटवारा भी परिणाम बदल सकता है। हालांकि, मतों का बंटवारा हमेशा एक ही दिशा में काम नहीं करता। किसी तीसरे दल की मौजूदगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है तो किसी दूसरी सीट पर कांग्रेस के वोट प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय दलों का उभार स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देकर बड़े दलों पर दबाव भी बना सकता है। इसलिए छोटे दलों की भूमिका का वास्तविक आकलन सीटवार राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

इस पूरे चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे अहम सवाल प्रत्याशी चयन का है। मजबूत संगठन के बावजूद यदि दोनों दल स्थानीय जनभावनाओं की अनदेखी करते हैं तो बागी उम्मीदवार उनके समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दूसरी ओर, यूकेडी, आप और उमेश कुमार की प्रस्तावित पार्टी के लिए भी केवल अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें भरोसेमंद चेहरों, स्थानीय मुद्दों और स्पष्ट राजनीतिक विकल्प के साथ जनता के बीच जाना होगा। उत्तराखंड का मतदाता अब तक सत्ता के मुख्य विकल्प के रूप में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही चुनाव करता आया है। तीसरी राजनीतिक ताकत की संभावनाएं तभी मजबूत होंगी, जब वह चुनाव के समय दिखाई देने वाली सक्रियता से आगे बढ़कर लगातार जनहित के मुद्दों पर काम करे और भरोसेमंद संगठन खड़ा करे।

2027 का चुनाव इसलिए केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं होगा। यह छोटे दलों की राजनीतिक प्रासंगिकता, नए नेतृत्व की स्वीकार्यता और राष्ट्रीय दलों की संगठनात्मक क्षमता की भी परीक्षा बनेगा। अंततः चुनावी परिणाम इस बात से तय होंगे कि कौन-सा दल जनता के असंतोष को विश्वसनीय विकल्प में बदल पाता है, कौन सही प्रत्याशी चुनता है और कौन टिकट वितरण के बाद अपने संगठन को एकजुट रख पाता है।

उत्तराखंड की सियासत में फिलहाल मुकाबले की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन असली तस्वीर उम्मीदवारों के नाम सामने आने और चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही स्पष्ट होगी।

क्या बाथ टॉवल बदलने का समय आ गया है? इन संकेतों से लगाएं पता

बाथ टॉवल का इस्तेमाल करने से त्वचा को सुखाने में मदद मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाथ टॉवल को कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल, बाथ टॉवल को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जो त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको अपना बाथ टॉवल बदल लेना चाहिए।

गंध आना : अगर आपके बाथ टॉवल में अजीब गंध आने लगे तो उसे तुरंत बदल दें। गीला बाथ टॉवल एक ऐसी जगह होती है, जहां कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जो त्वचा पर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आपके बाथ टॉवल में अजीब गंध आने लगे तो उसे तुरंत बदल दें। इसके अलावा इस्तेमाल किए हुए बाथ टॉवल को हमेशा खुली जगह पर सुखाएं ताकि उसमें मौजूद नमी दूर हो जाएं और कीटाणु न पनप सकें।

अगर बाथ टॉवल बहुत पतला हो गया हो तो उसे बदलें : अगर आपका बाथ टॉवल बहुत पतला हो गया है तो उसे बदलें। कई बार धोने के बाद बाथ टॉवल का कपड़ा ढीला और पतला हो जाता है, जिससे वह अपनी नमी को अच्छे से सोख नहीं पाता है। ऐसे बाथ टॉवल से त्वचा पर खरोंच भी आ सकती है, इसलिए अगर आपका बाथ टॉवल बहुत पतला हो गया हो तो उसे बदल लें।

दाग-धब्बे दिखाई दें तो बदलें बाथ टॉवल : अगर आपके बाथ टॉवल पर दाग-धब्बे दिखाई देने लगे तो उसे बदल लें। बाथटॉवल पर साबुन या शैंपू के दाग लगते हैं, जिन्हें धोने से साफ नहीं किया जा सकता है। अगर आपके बाथ टॉवल पर पसीने या गंदगी के दाग लगे हैं तो उसे भी बदल लें। इन दागों को साफ करने में काफी समय लग सकता है।

ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी नहीं दिख रहा है बदलाव : अगर आप अपने बाथ टॉवल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो उसे बदल लें। आमतौर पर इस्तेमाल के बाद बाथ टॉवल थोड़ा मुलायम और ज्यादा सोखने वाला हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह पुराना हो गया है।

इसके अलावा अगर बाथ टॉवल ज्यादा गीला रह रहा है तो उसे बदल लें।

ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना नहीं है सही : अधिकतर लोग अपने बाथ टॉवल को 2 साल तक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, हर 6-12 महीने में बाथ टॉवल को बदल लेना चाहिए, खासकर अगर आपके बाथ टॉवल पर कोई विशेष धारण जैसे कि रंग, डिजाइन या पैटर्न नहीं है। समय-समय पर अपने बाथ टॉवल को बदलना न केवल आपकी त्वचा बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसलिए हर 6-12 महीने में अपने बाथ टॉवल को बदल लें।

पहला होम जिम बनाने के लिए न खरीदें 12 मशीनें, इन 5 चीजों पर दें ध्यान

जिम के बिना फिटनेस पाना संभव है। इसके लिए आप अपने घर पर होम जिम बना सकते हैं। होम जिम बनाने के लिए आपको 12 मशीनों की जरूरत नहीं होती। कुछ जरूरी सामानों से ही आप अपना होम जिम बना सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अपनी फिटनेस को भी बेहतर बना सकेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी सामानों के बारे में बताते हैं, जो आपके होम जिम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

योगा मैट : योगा मैट एक जरूरी सामान है, जिसका उपयोग आप योगा, स्ट्रेचिंग या फर्श पर की जाने वाली कसरत के लिए कर सकते हैं। यह मैट आपके शरीर को आरामदायक महसूस कराने में मदद करता है और फर्श की कठोरता से बचाव करता है। इसके अलावा यह मैट आपको एक साफ और सुरक्षित जगह प्रदान करता है, जहां आप बिना किसी परेशानी के अपनी कसरत कर सकते हैं। योगा मैट के साथ घर पर ही फिटनेस का आनंद ले सकते हैं।

डंबल्स : डंबल्स सबसे जरूरी उपकरणों में से एक हैं, जिनका उपयोग आप अलग-अलग प्रकार की कसरत के लिए कर सकते हैं। डंबल्स से आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं और शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं। ये छोटे होते हैं और इन्हें संभालना आसान होता है, जिससे आप घर पर ही आराम से कसरत कर सकते हैं। डंबल्स का उपयोग करके आप कई प्रकार की कसरत कर सकते हैं, जैसे बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप एक्सटेंशन, शोल्डर प्रेस आदि।

कूदने वाली रस्सी : कूदने वाली रस्सी एक सरल लेकिन असरदार उपकरण है, जिससे आप दिल की सेहत और फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और आपका वजन नियंत्रित रहता है। कूदने वाली रस्सी का उपयोग करने से आपकी धड़कनें तेज होती हैं, जिससे आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है। यह उपकरण हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है।

एक्सरसाइज बॉल : एक्सरसाइज बॉल का उपयोग करके आप संतुलन, स्थिरता और ताकत बढ़ा सकते हैं। इससे कई प्रकार की कसरत की जा सकती हैं, जो पेट, पीठ और पैरों के लिए फायदेमंद होती हैं। इस बॉल पर बैठने से आपकी मुद्रा सुधरती है और मांसपेशियों पर दबाव कम होता है। यह बॉल आपके घर के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो सकती है और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फिटनेस को एक नया आयाम दे सकते हैं।

छींक या खांसी रोकना कैसे हो सकता है खतरनाक, किसे होता है सबसे ज्यादा खतरा

सर्दी या जुकाम होने के बाद छींक आना काफी आम होता है, कई लोगों को काफी ज्यादा छींक आती हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि कई बार बिना जुकाम के भी छींक आ जाती हैं, अक्सर एक के बाद दूसरी छींक भी तुरंत आती है। ऐसे में कई लोग अपनी छींक को आने से रोक लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे।।।

अक्सर छींकने से बचते हैं लोग

दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ऑफिस या फिर लोगों के सामने वो जोर से छींक मारें, इसीलिए वो अपनी छींक को रोक लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जब किसी के भी सामान्य तौर पर छींकने पर लोग उसकी तरफ घूरने लगते थे और दूरी बना लेते थे। ऐसे में लोग अपनी छींक को रोकना ही ठीक समझते थे।

छींक रोकने पर क्या होता है?

अब बात करते हैं कि आखिर छींक आने से रोकना क्यों खतरनाक हो सकता है और डॉक्टर ऐसा हर बार नहीं करने की सलाह क्यों देते हैं।।। दरअसल जब हम खांसते या फिर छींकते हैं तो शरीर में दबाव होता है, इससे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है। ऐसे में अगर कोई छींक रोकता है तो ये दबाव 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर के कमजोर हिस्सों में प्रेशर पडने से घाव हो सकता है। इससे कान और आंखों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि हर बार छींक या फिर खांसी को रोकना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अगर आपको छींक आ रही है तो आप रुमाल या फिर हाथ लगाकर छींक सकते हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर इतना दबाव झेलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन समस्या उन लोगों को हो सकती है जिनके शरीर में कमजोरी है। खासतौर पर शराब या सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए छींक को रोकना खतरनाक हो सकता है, ऐसा करने से उनकी सांस की नली या फिर फेफड़ों पर असर पड़ सकता है।

बच्चे में एकाग्रता की कमी इस प्रकार होगी ठीक

ज्यादातर बच्चों में देखा गया है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाकी कामों में भी वे सही से ध्यान नहीं दे पाते। इसकी कई वजहें हो सकती हैं लेकिन एक वजह एकाग्रता की कमी भी है।

अगर आपके बच्चे में भी एकाग्रता की कमी है तो फिर कुछ चीजों का ध्यान रख आप इसे सुधार सकते हैं।

नाश्ते में साबुत अनाज की बनी चीजें

आपका बच्चा किसी काम पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाता इसकी सबसे बड़ी वजह है उसके शरीर में शुगर की कमी। इसे पूरा करने के लिए अपने बच्चे को साबुत अनाज का नाश्ता दें। चाहे तो आप नाश्ते में ब्राउन राइस और बाजरे की बनी चीजें दे सकते हैं। ब्राउन राइस पोहा खिला सकते हैं। साबुत अनाज को नाश्ते में शामिल करने से दिनभर भूख नहीं लगती और पूरे दिन दिमाग भी सक्रिय रहता है।

जब बच्चे घर से बाहर होते हैं या बाहर खाते हैं तो फिर आप उनकी बॉडी के शुगर लेवल पर चेक नहीं रख सकते इसलिए जरूरी है कि आप उनकी शुगर क्रेविंग्स को घर पर ही दूर कर दें। इसके लिए आप अपने बच्चे को शुगर से शरीर में होने वाले नुकसान के बारे में बता सकते हैं। आपका बच्चा रोजाना जो खाना खा रहा है उसमें भी आप कुछ बदलाव कर उसके शरीर में शुगर की कमी पूरी कर सकते हैं।

आलू के बजाय अपने बच्चों को स्टार्च वाली अन्य चीजें खिलाएं जैसे कि शकरकंदी। इसे आप बेक्ड चिप्स और फ्रेंच फ्राइज भी बना सकती हैं। अगर आपके बच्चे को अरबी खाना पसंद नहीं है तो आप उससे अन्य स्वादिष्ट चीजें बना सकती हैं। इसके अलावा बाकी स्टार्च फूड्स खिला सकती हैं। दरअसल स्टार्च सेरोटॉनिन का मुख्य स्त्रोत होता है जो मूड को अच्छा रखता है। इसके अलावा यह बच्चों को शांत और खुश रहने में भी मदद करता है।

शब्द सामर्थ्य -070

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवाद, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (उ.) 11. किरण 12. छौंक, तड़का 13. दुखदायी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समूह, दल, समुदाय 19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध सफेद पक्षी, वक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।

ऊपर से नीचे

1. विचित्र, अद्भूत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुलायम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यावली, करस्तानी, प्रशंसनीय कार्य 13. दासी, नौकरानी, बांदी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (उ.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।

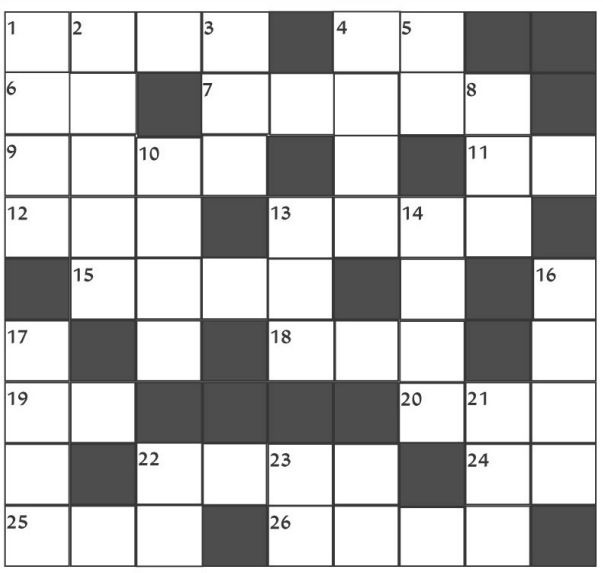

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 69 का हल

दि	क्क	त	■	आ	सा	न	■	आ
ल	■	मी	■	खि	■	सी	ख	ना
■	म	ज	बू	र	■	ह	■	जा
स	र्द	■	■	का	■	त	रा	ना
र	■	■	■	र	वि	■	ह	■
प	ह	ना	ना	■	ना	रा	ज	■
ट	■	■	क	शि	श	■	नी	ला
■	र	■	■	का	■	रा	■	य
खा	ति	र	दा	री	■	त	क्ष	क

कुणाल खेमू के शो अलायंस के दूसरे सीजन का ऐलान

अभिनेता कुणाल खेमू की मेजबानी वाले लोकप्रिय रियलिटी शो %अलायंस' के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। निर्माताओं ने शो के दूसरे सीजन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही नए सीजन के प्रसारण की तारीख भी तय कर दी गई है। यह शो 14 जनवरी, 2027 से अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित होगा।

जून 2026 में प्रसारित हुए पहले सीजन को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसी लोकप्रियता को देखते हुए निर्माताओं ने इसे दूसरे सीजन के साथ वापस लाने का फैसला किया है। पहले सीजन में डेजी शाह, अर्सलान गोनी, सोहेल खान, कुशाल टंडन और मैक्सटर्न समेत कुल 16 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगियों के बीच गठबंधन बनाने, रणनीति तैयार करने और एक-दूसरे को चुनौती देने के कारण यह शो चर्चा में रहा। पहले सीजन की विजेता मिनी माथुर बनी थीं।

अमेजन प्राइम वीडियो ने सामाजिक माध्यम %एक्स' पर आधिकारिक पोस्टर जारी कर दूसरे सीजन की घोषणा की। पोस्ट के साथ दिए गए संदेश में नए गठबंधनों, अधिक नाटकीय घटनाक्रम और गठबंधनों के टूटने का संकेत दिया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि नए सीजन में प्रतियोगियों के बीच रणनीतिक मुकाबला और रोमांच देखने को मिलेगा।

%अलायंस' की खासियत इसका गठबंधन, विश्वासघात और रणनीति पर आधारित प्रारूप है। इसमें प्रतियोगियों को परिस्थितियों के अनुसार दूसरे प्रतिभागियों के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है। हालांकि, बदलते समीकरणों के बीच इन गठबंधनों का टूटना भी खेल का अहम हिस्सा है।

अलायंस' टाल्पा स्टूडियोज के लोकप्रिय डच प्रारूप का पहला अंतरराष्ट्रीय रूपांतरण है। भारत में इसका निर्माण बनिजय एशिया ने किया है। शो में सामाजिक संबंधों, आपसी विश्वास, रणनीति और प्रतिस्पर्धा को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है।

पहले सीजन की सफलता के बाद अब दर्शकों की नजर इसके दूसरे सीजन पर है। 14 जनवरी, 2027 को होने वाले प्रीमियर के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि नए सीजन में कौन से प्रतियोगी शामिल होते हैं और गठबंधन तथा रणनीति का खेल किस तरह आगे बढ़ता है।

जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की काली खेती अब 20 नवंबर को होगी प्रदर्शित

अभिनेता जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की आगामी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित डरावनी फिल्म %काली खेती' की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन अब दर्शकों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। निर्माताओं ने नई रिलीज तारीख की घोषणा करते हुए फिल्म से दोनों अभिनेताओं के पहले रूप भी जारी किए हैं। अब यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

हारिस इम्तियाज खान के लेखन और निर्देशन में बनी %काली खेती' ग्रामीण जीवन और कृषि को डरावने तथा रहस्यमयी अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। फिल्म की कहानी गांव की पृष्ठभूमि में रची गई है, जहां खेती-किसानी से जुड़े परिवेश को भय और रहस्य के साथ जोड़ा गया है।

फिल्म के जारी किए गए पोस्टर में जैकी श्रॉफ का अधूरा और डरावना रूप दिखाई दे रहा है। वहीं, शरद केलकर गंभीर और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ इस्तेमाल की गई रहस्यमयी धुन फिल्म के भयावह वातावरण की झलक पेश करती है।

निर्माताओं ने इन झलकियों के जरिए फिल्म की रहस्यमयी दुनिया और उसके पात्रों के बारे में उत्सुकता बढ़ाने की कोशिश की है। ग्रामीण परिवेश में रची गई यह कहानी पारंपरिक डरावनी फिल्मों से अलग अंदाज में खेती और गांव की दुनिया को पर्दे पर प्रस्तुत करने का वादा करती है।

%काली खेती' में अभिनेत्री नेहा सरगम मुख्य महिला भूमिका में नजर आएंगी। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की मौजूदगी के साथ फिल्म में ग्रामीण जीवन, रहस्य और डर का मेल देखने को मिलेगा।

फिल्म की रिलीज तारीख में बदलाव के बाद अब यह 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। दर्शकों को उम्मीद है कि फिल्म की कहानी और कलाकारों के अलग-अलग रूप बड़े पर्दे पर एक नया अनुभव देंगे।

निजी दर्द को शब्दों में पिरोकर कादर खान ने लिखा था मुकद्दर का सिकंदर का यादगार सीन!

बॉलीवुड अभिनेता कादर खान ने अपने करियर में कभी विलेन बनकर दर्शकों को डराया, तो कभी कॉमेडी से हंसाया। वहीं अपनी लेखनी से अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के किरदारों को खास पहचान भी दी लेकिन फिल्मों में आने से पहले कादर खान की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और पढ़ाने के साथ थिएटर में भी एक्टिव रहते थे। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित डायलॉग राइटर्स में शामिल कर दिया।

कादर खान के लिखे डायलॉग्स की ताकत का एक बड़ा उदाहरण 1978 में रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का 16 पन्नों वाला सीन है। कादर खान ने इस सीन में अपने जीवन के अनुभवों को उतार दिया था। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को इसे सुनाया तो बिग बी इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। कादर खान का जन्म 1937 में काबुल में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां उन्होंने मुश्किल हालात में अपना बचपन बिताया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई के एमएच साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक में लेक्चरर रहे और उन्हें बेस्ट टीचर का अवॉर्ड भी मिला लेकिन पढ़ाने के साथ-साथ एक्टिंग और डायलॉग लिखने का शौक उनके भीतर बना रहा। वह थिएटर में हिस्सा लेते थे और स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखाते थे। इसी दौरान एक नाटक में उनके काम ने लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें फिल्मों के लिए डायलॉग लिखने का मौका मिला।

कादर खान ने 1970 के दशक की शुरुआत में फिल्मों के लिए डायलॉग लिखना शुरू किया। 1972 में आई फिल्म जवानी दीवानी को उनके शुरुआती फिल्मी लेखन के अहम पड़ाव के तौर पर याद

किया जाता है। इसके बाद राजेश खन्ना की फिल्म रोटी ने उनके करियर को नई पहचान दी।

मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर्स के साथ उनके काम ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत जगह दिलाई। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नसीब और कुली जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे। उनकी खासियत यह थी कि वह किरदार के हिसाब से भाषा और अंदाज बदल लेते थे। उनके डायलॉग में कहीं इमोशन था, कहीं गुस्सा और कहीं ऐसा मजाक, जो सीधे दर्शकों से जुड़ जाता था।

कादर खान के करियर का एक यादगार किस्सा फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ा है। उन्होंने बताया था कि फिल्म में एक सीन था, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार स्टेज पर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। इस सीन को लिखते समय कादर खान ने अपने निजी जीवन के अनुभवों को भी शामिल किया था। यही वजह थी कि वह इस सीन को लेकर काफी भावुक थे। जब उन्होंने इसे फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा को सुनाया तो वह भी भावुक हो गए थे।

लेकिन जब यह स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो 16 पन्नों का सीन देखकर वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इतने लंबे डायलॉग याद करना और उन्हें पर्दे पर सही भाव के साथ बोलना मुश्किल होगा। उन्होंने सीन को छोटा करने की बात कही। कादर खान उस वक्त दूसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। फिर अमिताभ बच्चन की तरफ से उन्हें बुलावा आया। कादर खान को लगा कि शायद उनके सीन में कोई कमी निकाली गई है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें अपनी बात समझाने का मौका मिला।

कादर खान ने इंटरव्यू में बताया था कि जब वह अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे तो उन्होंने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और खुद पूरा सीन पढ़कर सुनाना शुरू किया। जैसे-जैसे कादर खान अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभवों को शब्दों में उतारते गए, सीन का इमोशनल असर सामने आता गया। कादर खान के मुताबिक, पूरा सीन सुनते-सुनते अमिताभ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ लंबे डायलॉग नहीं हैं, बल्कि किरदार की जिंदगी और दर्द को बयान करने वाले शब्द हैं। इसके बाद अमिताभ ने कादर खान से कहा कि वह आगे भी अपनी आवाज में सीन रिकॉर्ड करके दिया करें, क्योंकि उनके सुनाने का अंदाज डायलॉग के भाव समझने में मदद करता था।

कादर खान की पहचान सिर्फ डायलॉग राइटर तक सीमित नहीं रही। 1973 में फिल्म दाग से बतौर एक्टर उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। गोविंदा के साथ उनकी कॉमेडी वाली फिल्मों ने 1990 के दशक में उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी लोकप्रिय बनाया। दुल्हे राजा, कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग खूब पसंद की गई।

एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर को पर्दे पर दुल्हन बनना पसंद

टीवी एक्ट्रेस प्रिया ठाकुर इन दिनों अपने शो वसुधा में देव और वसुधा की शादी के ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं। जी टीवी के इस शो में दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है। शादी के इस ट्रैक को लेकर प्रिया ने बताया कि पर्दे पर दुल्हन बनना उन्हें हमेशा पसंद रहा है, हालांकि भारी लहंगे, जूलरी और घंटों तक शूटिंग करना आसान नहीं होता। शो में देव और वसुधा की शादी पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार उनकी शादी का मतलब दोनों के लिए काफी अलग है। इसकी सबसे बड़ी वजह चंद्रिका का वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करना है। दर्शक लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे और अब पूरे परिवार को दोनों के रिश्ते का जश्न मनाते देखना उनके लिए खास होगा।

प्रिया ने कहा, शो में शादी से जुड़े कई शानदार फंक्शन दिखाए गए हैं और यह उन सभी फैंस के लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिन्होंने देव और वसुधा के सफर में उनका साथ दिया है। शादी के ट्रैक की शूटिंग हमेशा मजेदार होती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। भारी कपड़े, जूलरी और सेट पर लंबे समय तक काम करना आसान नहीं होता। मुझे स्क्रीन पर दुल्हन बनना हमेशा पसंद रहा है। मुझे खूबसूरत और रॉयल आउटफिट्स के साथ जूलरी पहनना अच्छा लगता है, हालांकि उन्हें लंबे समय तक संभालकर रखना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, इस पूरे ट्रैक की शूटिंग का अनुभव शानदार रहा है। मुझे यकीन है कि दर्शकों को देव और वसुधा की जिंदगी के इस नए सफर को देखना पसंद आएगा।

देव का किरदार निभाने वाले अभिषेक शर्मा भी इस शादी के ट्रैक को लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि देव और वसुधा को आखिरकार उनकी खुशियों भरी जिंदगी मिल रही है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शादी के ट्रैक की शूटिंग काफी एक्साइटिंग होती है। हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है, जिससे पूरा काम आसान और मजेदार बन जाता है। पूरी कास्ट भी काफी प्रोफेशनल और सपोर्टिव है।

खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले जांचें गुणवत्ता, पैकिंग और एक्सपायरी डेट

हरिद्वार (आरएनएस)। त्योहारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आशंका के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से खरीदारी में सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं, मिलावट के मामलों में कार्रवाई के बावजूद पिछले करीब एक साल में सजा सुनाए जाने के दो ही मामले सामने आए हैं। दोनों मामले पनीर बनाने वाली इकाइयों से जुड़े हैं। सीजेएम कोर्ट ने इनके संचालकों को छह-छह माह की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि तीन अक्टूबर को नन्हेड़ा अनंतपुर स्थित इकाई पर छापेमारी की गई थी। वहां दो कुंतल अधबना पनीर, 20 किलो पामोलिन तेल और 30 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला था। विभाग ने अधबना पनीर और पाम ऑयल नष्ट करा दिया था। वहीं, 13 अक्तूबर को लक्सर के संघीपुर गढ़ी स्थित इकाई में करीब तीन कुंतल तैयार पनीर और छह कुंतल अधनिर्मित पनीर मिला था। मौके पर पाम ऑयल के टिन और स्किम्ड मिल्क पाउडर के खाली बोरे भी बरामद हुए थे। विभाग ने करीब 10 कुंतल खाद्य पदार्थ नष्ट कराकर इकाई बंद करा दी थी। खाद्य अनुज्ञप्ति भी निलंबित कर दी गई थी। अधिकारी के अनुसार, दोनों मामलों में न्यायालय संचालकों को सजा सुना चुका है।

खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ताओं को पैकेट पर निर्माता का नाम-पता, सामग्री की सूची, निर्माण या पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का अनुज्ञप्ति नंबर जांचना चाहिए। पैकिंग फटी हो या जरूरी जानकारी स्पष्ट न हो तो उत्पाद खरीदने से बचें। केवल रंग, गंध, स्वाद या बनावट के आधार पर किसी खाद्य पदार्थ को शुद्ध अथवा मिलावटी नहीं माना जा सकता। खुले में बिकने वाली मिठाइयों, मावा और पनीर की खरीदारी में साफ-सफाई और भंडारण की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। अनुज्ञप्ति नंबर होने मात्र से उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी नहीं मिलती। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह होने या मिलावट की आशंका पर उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए एफएसएसएआई की ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा कनेक्ट मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत के समय दुकान का नाम-पता, खाद्य पदार्थ का विवरण, पैकेट की तस्वीर, अनुज्ञप्ति नंबर और खरीदारी का बिल देना उपयोगी होगा। महिमानंद जोशी के अनुसार, शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी जांच कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर खाद्य पदार्थ का नमूना लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001804246 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय या क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी शिकायत दी जा सकती है?

सू- दोकू क्र.070

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.69 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

मिलावट से लीवर-किडनी पर खतरा, गर्भस्थ शिशु के विकास पर भी असर

हल्द्वानी(आरएनएस)। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले हानिकारक रसायन और दूसरे पदार्थ पाचन तंत्र को प्रभावित करने के साथ लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोजमर्रा की थाली में शामिल दूध, मावा, पनीर, घी, मसाले, फल और सब्जियां सेहत बनाने के बजाय बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। मिलावटी और दूषित भोजन से उल्टी-दस्त, संक्रमण और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से गर्भस्थ शिशु का विकास प्रभावित होने का जोखिम बढ़ जाता है। दूध-मावे से मसालों तक मिलावट का खतरा

गर्भावस्था के दौरान दूषित या हानिकारक रसायनों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन मां के साथ गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में शिशु के अंगों का विकास तेजी से होता है। इस दौरान कुछ हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से विकास प्रभावित होने और समय से पहले प्रसव जैसी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। तंत्रिका तंत्र समेत शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर पड़ता है।

स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट हल्द्वानी के निदेशक डॉ. केसी पांडे ने बताया कि कैंसर अलग-अलग कारणों से होता है। सबसे अधिक तंबाकू और शराब के सेवन से कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों से भी कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। मिलावटी खाद्य पदार्थों में कई ऐसे रसायन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर वह लंबे समय तक खाए जाते हैं तो यह लीवर, किडनी समेत कई अंगों को प्रभावित करते हैं। धीरे-धीरे कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।

राजकीय मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. पंकज वर्मा ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से सबसे पहले पेट संबंधी बीमारियां शुरू होती हैं। उल्टी-दस्त, फूड पॉइजनिंग, संक्रमण के मामले सामने आते हैं और धीरे-धीरे लीवर और किडनी जैसे अंगों के फेलियर जैसे मामले सामने आ सकते हैं। अमाशय में गंभीर शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। धीरे-धीरे मल्टीपल अंगों पर प्रभाव शुरू हो जाता है।

बेस अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएस रावत ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में वह जल्दी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अगर बच्चों को मिलावटी दूध दिया जाए तो वह बहुत जल्दी उल्टी-दस्त, फूड पॉइजनिंग, संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। रसायनयुक्त और मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने मल्टीपल ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं। अक्सर डायरिया की शिकायतें आती रहती हैं।

राजकीय महिला अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. अखिलेश ने बताया कि मिलावटी तेल के उपयोग से धीरे-धीरे नशों में खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे हाईअटैक की आशंका बढ़ जाती है। वहीं मिलावटी शुगर की वजह से ट्रॉइक्लोसाइड बढ़ता है। मिठाइयों में सिल्वर फॉल (वर्क) भी सेहत के लिए खतरनाक है। सिल्वर फॉल लगी मिठाइयों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

आलू फल व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश जोशी का कहना है कि मंडी में कई प्रकार की सब्जियां बाहर से आयात की जाती हैं, फूल विदेशों से आता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए कोटिंग की जाती है। सब्जियों में कृत्रिम रंग की जांच को लेकर कारोबारी अक्सर मंडी प्रशासन से शिकायत करते रहते हैं। कार्रवाई भी होती है, लेकिन मिलावट रोकने को लेकर और सख्ती बरतने की जरूरत है।

सुरक्षा गार्ड ही निकला मनचला

रुद्रपुर(आरएनएस)। आचार्य भवन से ड्यूटी कर घर लौट रही एक महिला के साथ पंतनगर इंटर कॉलेज के पास सुनसान सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने सुरक्षा विभाग में शिकायती पत्र देकर गार्ड पर पीछा करने, गलत तरीके से छूने और विरोध करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब नौ बजे पंतनगर परिसर निवासी 30 वर्षीय महिला आचार्य भवन से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी। आरोप है कि पंतनगर इंटर कॉलेज के पास सुनसान सड़क पर सुरक्षा विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत 35 वर्षीय युवक ने उसका पीछा किया।

स्कूल में व्यावसायिक विषय बदलने की मांग उठाई

नई टिहरी(आरएनएस)। जाखणीधार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट के अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजकर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तृतीय चरण के तहत चयनित विषय को बदलने की मांग उठाई है।

पीटीए अध्यक्ष भट्ट ने विधायक और सीईओ से छात्रहित में विषय परिवर्तन की मांग की है। बताया कि स्कूल के निकट टिहरी बांध की झील होने से उसमें टूरिज्म से संबंधित अनेक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं।

छात्र-छात्राओं को विद्यालय में प्रोफेशनल विषय के तहत टूरिज्म संबंधित जानकारी दी जाती है तो भविष्य में छात्रों के लिए यह स्वरोजगार और रोजगार में सहायक सिद्ध होगा। विधायक उपाध्याय ने प्रकरण में सीईओ को उचित कार्रवाई को कहा है। इस बाबत मुख्य शिक्षा अधिकारी कमला बडवाल का कहना कि शिक्षा सत्र आधा बीत चुका है। बावजूद इसके अभिभावक यदि विद्यालय को आवंटित व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय को परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाएं।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत नगर के तीन विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को लैंगिक शोषण से बचाव, बाल अधिकारों, साइबर सुरक्षा और नि:शुल्क कानूनी सहायता सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल और विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवनधाम में आयोजित शिविरों में परिवार न्यायालय की न्यायाधीश अंजुश्री जुयाल ने विद्यार्थियों को लैंगिक शोषण और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने नालसा की बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024 और पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न, बाल विवाह निषेध, बाल श्रम, बाल तस्करी, असुरक्षित स्पर्श, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और बच्चों को प्राप्त विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने मेरा बचपन मेरा अधिकार, बोलो, बताओ, बचाओ, कानून जानो, बचपन बचाओ और जागरूक बचपन-सशक्त भारत जैसे संदेशों के माध्यम से बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही किसी भी प्रकार के शोषण या असुरक्षित परिस्थिति में चुप न रहने और सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। शिविर में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देने के साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध नि:शुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुरक्षित बचपन अभियान से संबंधित जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। शिविरों में रिटेनर अधिवक्ता, अधिकार मित्र सहित विद्यालयों के विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

6 पेटी अंग्रेजी शराब व एक पेटी बियर सहित तस्कर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

टिहरी। पहाड़ो में शराब तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से 6 पेटी अंग्रेजी शराव व एक पेटी बियर बरामद हुई है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज कोतवाली चंबा पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कोई शराब तस्कर शराब की डिलीवरी हेतू आने वाला है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को जसपुर तिराहे के समीप कार सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो वह कार छोड़कर भागने लगा। इस पर उसे घेर कर दबोचा गया। कार की तलाशी के दौरान उसमें रखी 6 पेटी अंग्रेजी शराब व एक पेटी बियर बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज पुत्र ओमपाल, निवासी कोटी कॉलोनी, बीपुरम, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधि नियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शराब तस्करी में पकड़े गये वाहन को सीज कर दिया है।

सड़कों पर वीआईपी वाहन-फुटपाथ.... ◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

केंद्र होना नहीं है। राजधानी की असली पहचान इस बात से बनती है कि वहां आम नागरिक कितनी आसानी से, सुरक्षित ढंग से और सम्मान के साथ आवागमन कर सकता है। सड़कें किसी रसूखदार की निजी पार्किंग नहीं और फुटपाथ किसी दुकानदार की निजी संपत्ति नहीं हैं। दोनों पर पहला अधिकार सार्वजनिक उपयोग का है। देहरादून की सड़कों पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहर की सड़कें और फुटपाथ आम जनता के लिए हैं, या उनका इस्तेमाल वही करेगा जिसके पास रसूख है या जो नियमों को ताक पर रख सकता है? जब तक इस सवाल का जवाब कार्रवाई के रूप में नहीं मिलता, तब तक आम आदमी जाम में फंसता रहेगा और राजधानी की यातायात व्यवस्था बदहाली की कीमत उससे वसूलती रहेगी।

चुनाव आते ही निशाने पर कांग्रेस का.... ◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

पारदर्शिता, जांच और जवाबदेही के लिए उसकी नीति क्या होगी। केवल भाजपा पर हमला करने से वह अपने राजनीतिक अतीत से जुड़े प्रश्नों से मुक्त नहीं हो सकती।

धामी सरकार के सामने भी सवाल कम नहीं हैं। कांग्रेस के शासनकाल के विवादों का उल्लेख करना राजनीतिक रूप से प्रभावी हो सकता है, लेकिन इससे वर्तमान सरकार के खिलाफ उठने वाले सवाल समाप्त नहीं होते। भाजपा को यह बताना होगा कि उसके शासन में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, जांच कितनी आगे बढ़ी और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। यदि मुख्यमंत्री अपनी सरकार को घोटालों से मुक्त बताते हैं, तो इस दावे की विश्वसनीयता केवल राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था और निष्पक्ष कार्रवाई से मजबूत होगी। इसी तरह कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का मूल्यांकन भी प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। दोनों दलों के लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए आरोप किसी पर भी हों, जांच निष्पक्ष हो और जवाबदेही तय हो।

उत्तराखंड में 2027 का चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई भी बनने जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के पुराने विवादों को सामने रखकर सत्ता में वापसी की जमीन मजबूत करना चाहेगी। कांग्रेस मौजूदा सरकार के कामकाज, रोजगार, पलायन, महंगाई और शासन से जुड़े सवालों के आधार पर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश करेगी। लेकिन चुनावी रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राजनीतिक दल जनता की प्राथमिकताओं से कितना जुड़ते हैं। भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर मतदाता के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पलायन और स्थानीय विकास भी उतने ही अहम हैं। केवल एक-दूसरे के अतीत को उछालने से इन सवालों का समाधान नहीं निकलता। धामी ने भराड़ीसैंण से कांग्रेस को उसके अतीत का हिसाब देने की चुनौती दी है। अब भाजपा को अपने वर्तमान का हिसाब देना होगा और कांग्रेस को अपने आरोपों के प्रमाण सामने रखने होंगे। 2027 की चुनावी लड़ाई में निर्णायक बढ़त उसी पक्ष को मिल सकती है, जो आरोपों के शोर से आगे बढ़कर अपने दावों की विश्वसनीयता साबित करे। सदन में सियासी वार शुरू हो चुका है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला न मुख्यमंत्री के तीखे बयान से होता है, न विपक्ष की नारेबाजी से। फैसला इस बात से होता है कि जनता के सवालों का जवाब किसने दिया, किसके दावे तथ्यों पर टिके और किसने जवाबदेही से बचने के बजाय उसका सामना किया।

पुलिस कर्मियों एवं पीआरडी जवानों के स्वास्थ्य परीक्षण को लगाया मेडिकल कैंप

संवाददाता

टिहरी। पुलिस कर्मियों एवं पीआरडी जवानों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल कैम्प लगाया गया।

आज यहां पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हुए आज थाना छाम परिसर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंडीसौड़ से पहुंचे चिकित्सकों की टीम द्वारा थाना छाम में नियुक्त पुलिस कर्मियों एवं पीआरडी जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेडिकल कैंप के दौरान चिकित्सकों द्वारा पुलिस कर्मियों एवं पीआरडी जवानों के स्वास्थ्य की जांच कर उनके सामान्य स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति का आकलन किया गया।

इस दौरान थाना छाम में नियुक्त कार्मिकों एवं पीआरडी जवानों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व को बढ़ावा देना है, ताकि पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी तत्परता, ऊर्जा एवं कार्यक्षमता के साथ कर सकें। चिकित्सकों द्वारा पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, पर्याप्त नींद सुनिश्चित करने तथा नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी गई। पुलिस की व्यस्त एवं चुनौतीपूर्ण ड्यूटी को देखते हुए कार्मिकों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के महत्व से अवगत कराया गया। नियमित दिनचर्या, उचित खानपान एवं तनाव प्रबंधन को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।

पुलिस कर्मी दिन-रात कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं, आपातकालीन परिस्थितियों एवं अन्य चुनौतीपूर्ण स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए पुलिस कर्मियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुलिस कर्मियों एवं सहयोगी बल के स्वास्थ्य की देखभाल, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की पहल की जा रही है। पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वस्थ कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु भविष्य में भी इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

दो नशा तस्कर गिरफ्तार, लाखों रुपये की स्मैक बरामद

हमारे संवाददाता

देहरादून। नशा तस्करी में लिप्त दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से चार लाख रूपये से अधिक की स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व में भी नशा तस्करी के कई मामलों में जेल जा चुका है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज नशा तस्करी की एक सूचना के बाद पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को 7.77 ग्राम स्मैक व स्मैक बेचकर कमाए 20000 रूपये की नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि जल्दी पैसा कमाने के लालच में वह मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो गया था तथा बरामद स्मैक को वह सहारनपुर से खरीद कर लाया था, जिसे वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में नशे के आदी स्थानीय व्यक्तियों को ऊंचे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुरसलीन पुत्र अब्बास निवासी शेखपुरा कदीम सहारनपुर, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है।

वहीं कोतवाली रायवाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान प्रतीत नगर तिराहे से पुरानी रायवाला रोड पर पुराने रेलवे अण्डरपास के पास से आरोपी राकेश बिन्द पुत्र अलगू शंकर को 7.50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया कि वह गाडी चलाने का काम करता है।

करवा चौथ भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक हैः थापर

हमारे संवाददाता

देहरादून। करवा चौथ के पावन पर्व के अवसर पर आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़, विजय पार्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर द्वारा महिलाओं के लिए मेहंदी कैंपों का आयोजन करवाया गया। इन कैंपों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाकर करवा चौथ के पर्व की खुशियां साझा कीं।

इस अवसर पर महिलाओं ने अभिनव थापर को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हुए अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया। मेहंदी कैंपों के माध्यम से महिलाओं के बीच आपसी मेल-मिलाप, उत्साह और पारंपरिक संस्कृति के प्रति जुड़ाव का सुंदर वातावरण देखने को मिला।

अभिनव थापर ने कहा कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं के साथ खुशियां साझा करना, हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करना तथा समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि एवं खुशहाल जीवन की कामना की।

गोविंदगढ़ में आयोजित मेहंदी कैंप में पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष अमृता कौशल व गुरचरण कौशल ने आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैम्प में विनीता जोशी, गीता देवी, विशाखा, जसनीत कौर जस्सल, सिमरन, ममता अरोड़ा, प्रीति रावत, रेणु अरोड़ा, रंजना पंत सहित अन्य महिलाओं ने मेहंदी कैम्प का लाभ लिया।

यूपी में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने पर होगी सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत!

नगर संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नियमों को सख्त कर दिया है। यदि कोई अभ्यर्थी हिंसक प्रदर्शनों या 'रिजीम चेंज' (हिंसक तरीकों से सत्ता परिवर्तन) जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा।

यूपी मे आवेदकों के चरित्र सत्यापन को लेकर नीति और सख्त की गई है, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर ही किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है।

नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उसे नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। सिर्फ एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से भी अभ्यर्थी स्वत: अयोग्य नहीं होगा।

नई व्यवस्था के तहत ऐसे अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था को बदलने की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हत्या, डकैती, दुष्कर्म, महिला की गरिमा भंग करने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे गंभीर मामलों में शामिल पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंसक गतिविधियों के जरिए व्यवस्था बदलने के उद्देश्य से काम करने वाले संगठनों से जुड़ाव भी सत्यापन के दौरान अहम माना जाएगा।

सरकार ने चरित्र सत्यापन में राजनीतिक विचारधारा और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट किया है। किसी अभ्यर्थी के राजनीतिक विचार या शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को अपने आप अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह, केवल एफआईआर दर्ज होने या किसी मामले की जांच लंबित होने से भी अभ्यर्थी को स्वत: सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। फैसला निर्धारित नियमों और सत्यापन में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।

नियमों में उम्र और गतिविधियों की समय-सीमा को लेकर भी प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक, 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद जांच की तारीख से पिछले तीन वर्षों के भीतर 'रीजिम चेंज' वाली गतिविधि में भाग लेने को इस बात का प्रमाण माना जाएगा कि व्यक्ति अब भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है।

नई व्यवस्था के तहत पुलिस को अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया के दौरान सत्यापन में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभाग अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

ये निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत होने वाले चयन में चरित्र सत्यापन पर लागू होंगे।

केदारनाथ धाम व गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू

❑बर्फबारी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज

हमारे संवाददाता

रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारधाम व गंगोत्री धाम में मौसम के करवट लेते हुए बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिरने से पूरा क्षेत्र सर्द हो गया है। बर्फबारी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

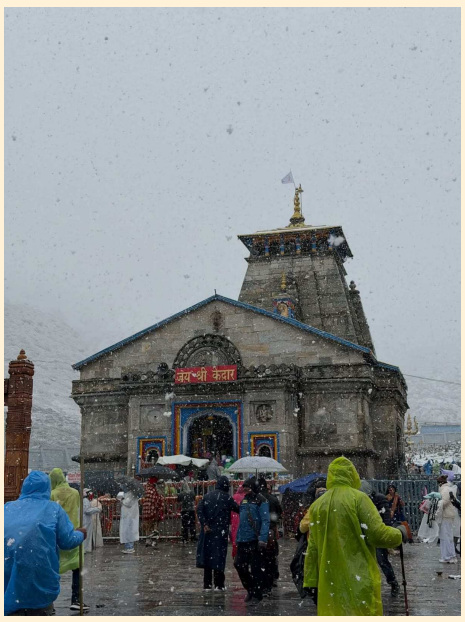

केदारधाम व गंगोत्री धाम में बर्फबारी का दौर शुरू होने से यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और निखर उठा है। दोनो मंदिर परिसरों तथा आसपास की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकने लगी हैं। मौसम के इस बदलाव से स्थानीय लोगों के साथ ही धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से भी निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। केदारनाथ धाम व गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी ने जहां सर्दी का अहसास बढ़ा दिया है, वहीं हिमालयी क्षेत्र में शीतकाल के आगमन का संकेत भी दे दिया है।

पति-पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत

हमारे संवाददाता

देहरादून। नेशनल हाईवे-74 पर दोराहा के पास बीते रोज बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई। ब्रिज ओवर के नजदीक पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम कनौरा निवासी 48 वर्षीय मुन्नालाल पत्नी जोसमीन के साथ बाइक से केलाखेड़ा रिश्तेदारी में जा रहे थे। रास्ते में दोराहा के पास नेशनल हाईवे-74 पर ओवरब्रिज के नजदीक पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ देर में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में चार बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। आनन-फानन में ही कोतवाल नरेश चौहान और दोराहा चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह मेहता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने और हादसे के बाद फरार चालक की तलाश में जुटी है।

शक्ति नहर से शव बरामद

हमारे संवाददाता

देहरादून। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ ने शक्ति नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला पुलिस को सौंप दिया गया है।

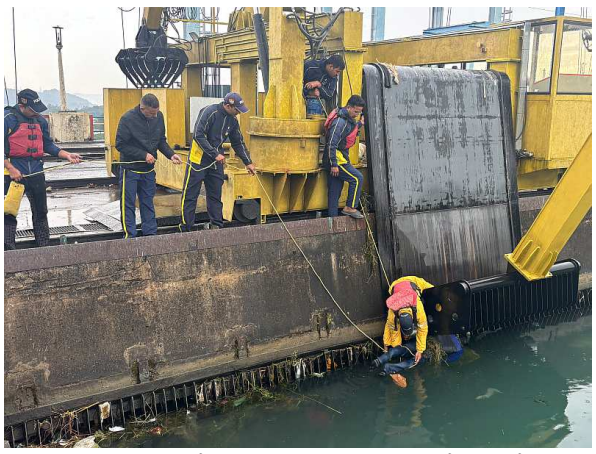

जानकारी के अनुसार आज सुबह कोतवाली विकासनगर से पोस्ट डाकपत्थर को सूचना प्राप्त हुई कि शक्ति नहर के समीप एक व्यक्ति नहर में कूद गया है। सूचना पर सर्च एवं रेस्क्यू कार्य हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता बताई गई। सूचना प्राप्त होते ही अपर उप निरीक्षक आशिक अली के हमराह एसडीआरएफ पोस्ट डाकपत्थर की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम द्वारा शक्ति नहर में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान एसडीआरएफ टीम ने ढालीपुर इंटेक से एक व्यक्ति का शव बरामद किया। इसके उपरांत शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा मृतक की पहचान विमल धीमान पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह धीमान, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम पोंदा, नंदा की चौकी के पास, प्रेमनगर, देहरादून के रूप में की गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्च अभियान पूर्ण किया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 11 लोग गिरफ्तार

संवाददाता

टिहरी। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 हजार रूपये नगद व ताश के पत्ते बरामद कर लिये। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में टिहरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी टिहरी के पर्यवेक्षण में थाना हिंडोलाखाल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 हजार रूपये की नकदी एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा सभी 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना हिंडोलाखाल पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में उन्होंने अपने नाम चंदन सिंह, पुत्र गोविंद सिंह, निवासी लालूखाल, पट्टी चंद्रबदनी, थाना हिंडोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल, विकास पुत्र ऋषिराम सेमवाल, निवासी ग्राम अंजनीसैंण, थाना हिंडोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल, रवि लाल, पुत्र नत्थी लाल, निवासी ग्राम अंजनीसैंण, थाना हिंडोलाखाल, जनपद टिहरी गढ़वाल, राहुल नेगी, पुत्र सुभाष नेगी, निवासी ग्राम गजा, थाना नरेंद्रनगर, रवि, पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी ग्राम सिम्बल, जिला फतेहगढ़, हरियाणा, हाल निवासी चाका लसेर, थाना हिंडोलाखाल, राज कुमार, पुत्र भगवान सिंह, निवासी चाका गजा, थाना नरेंद्रनगर, कैलाश सिंह, पुत्र जगदीश सिंह, निवासी ग्राम बनाली, थाना लंबगांव, प्रेम सिंह, पुत्र मेल सिंह, निवासी ग्राम चपोली, थाना हिंडोलाखाल, सोबन, पुत्र हीरा सिंह, निवासी ग्राम खरसाड़ा, थाना देवप्रयाग, हरि सिंह, पुत्र चंद्र सिंह, निवासी ग्राम चपोली, थाना हिंडोलाखाल, विनोद, पुत्र मदन सिंह, निवासी अंजनीसैंण, थाना हिंडोलाखाल बताये।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।